**कृपया प्रकाशनार्थ** **18 फरवरी 2009**

# पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राम नाईक व झोपडपछी बचाव समिति, कांदिवली पश्चिम के संयोजक श्री.बाबा सिंह द्वारा 18 फरवरी 2009 को मुंबई में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में दिया गया वक्तव्य

## *चारकोप मेट्रो के लिए निविदा न किए जाने का कारण जनता द्वारा किया जानेवाला कारशेड का विरोध - राम नाईक*

**मुंबई, बुधवार** : "मेट्रो रेल्वे के चारकोप-मानखुर्द मार्ग के लिए तीन बार निविदा मंगाने के बाद भी किसी कंपनी ने भी निविदा नहीं भरी. इसका कारण मंदी है तथा साथ ही निविदा करने को इच्छुक कंपनियों में आपसी कुछ अंतर्निहित कारण है, ऐसा एमएमआरडीए व महाराष्ट्र सरकार का कहना है.लेकिन असली कारण कुछ और है. वो है स्थानीय नागरिकों द्वारा चारकोप कारशेड प्रकल्प का जबरदस्त विरोध. इस तथ्य को एमएमआरडीए व महाराष्ट्र सरकार को ध्यान में रखना चाहिए ," इस प्रकार का संयुक्त बयान पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राम नाईक व झोपडपट्टी बचाव समिति, कांदिवली पश्चिम के संयोजक श्री.बाबा सिंह ने आज पत्रकारों के सामने दिया.

इस प्रस्तावित चारकोप मेट्रो कार शेड के संबंध में आगे बताते हुए श्री.राम नाईक ने कहा, "एमएमआरडीए द्वारा चारकोप में प्रस्तावित कारशेड के कारण संजयनगर, लालजीपाडा, गांधीनगर, एकता नगर, जनता कॉलनी आदि झोपडपट्टीयों में रहनेवाले तीस हजार से भी अधिक नागरिक बेघर हो जाएंगे. इसलिए इस कारशेड की जगह बदली जाय इस प्रकार की मांग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी, मनसे, रिपब्लिकन पार्टी, आदि सभी राजनीतिक पक्षों ने तथा अन्य स्थानीय सामाजिक संगठनों ने, एक होकर झोपडपट्टी बचाव समिति की स्थापन कर जनआंदोलन शुरू किया है. समिति की तरफ से हजारो नागरिकों ने हस्ताक्षर कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को निवेदन भेजकर प्रस्तावित कारशेड की जगह को बदलने की विनती भी की गई है . इसके लिए वैकल्पिक खाली जगह भी उपलब्ध है, इस बात का भी समिति ने सुझाव दिया था. इस विषय में चर्चा करने के लिए पिछले दो महीने में मुख्यमंत्री श्री अशोक चव्हाण के पास तीन पत्र लिखकर समय मांगा गया. पर आज तक मुख्यमंत्री ने एक पत्र का जवाब भी नहीं दिया, चर्चा करने के लिए समय देने की बात तो दूर है. इसके अलावा इस संदर्भ में सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना पर उठाए आक्षेपों पर भी कोई कारवाई नहीं हुई है. इस जगह पर एमएमआरडीए के अधिकारी जब सर्वेक्षण के लिए आए थे तब यहां के लोगों ने स्वत:स्फुर्त एकत्रित होकर इसका जबरदस्त विरोध किया था और अधिकारी सर्वेक्षण नहीं कर पाए थे. जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाता यहां मेट्रो कार शेड बनना मुश्किल है, इस बात को सभी संभावित निविदाकर्ता जानते हैं. इसलिए इस प्रकल्प के लिए निविदा भरने के लिए कंपनियां सामने नहीं आईं."

इस प्रकल्प के लिए जब तीन तीन बार निविदा नहीं भरी गई तो अब फिर एक बार निविदा मंगाने की योजना है ऐसा एमएमआरडीए ने कहा है. इस मेट्रो मार्ग के लिए केंद्र सरकार के द्वारा रु.1,532 करोड़ की राशि देने के बाद भी यह काम शुरू नही हो सका है, यह दुर्भाग्य की बात है. "एमएमआरडी का अधिकारी वर्ग व राज्य सरकार द्वारा निविदा न भरे जाने के पीछे मंदी और कंपनियों के आपसीं कुछ अंतर्निहित कारणों को न गिनाकर उन्हें आत्ममंथन करनी चाहिए और जनभावना का आदर करते हुए उनकी न्याय बात समझनी चाहिए. महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक इन प्रकल्प पीडितों के पुनवर्सन के संबंध में कोई नीति भी अभी तक नहीं बनाई है. प्रत्यक्ष काम शुरु करने से पहले कारशेड की जगह बदलें तभी मेट्रो का काम पूर्ण हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है. जनता का विरोध जानते हुए भी कंपनीयां व्यावसायिक खतरा मोल कर निविदा भरेगी इस भ्रम में सरकार ने नही रहना चाहिए. सरकार की इच्छा इस प्रकल्प की हालत कहीं 'सिंगुर' जैसी तो नहीं करनी है ?" ऐसा सवाल उठाते हुए अंत में श्री नाईक ने गहरी टिप्पणी की.

इस अवसर पर श्री.नाईक और श्री.बाबा सिंह के साथ झोपडपट्टी बचाव समिती के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे.

**(बाबा सिंह)के लिए**